स्वायत्ता बचाने कृषक परम्परागत ज्ञान नई तकनीकी में ढ़ालें: बन्धोपाध्याय

देहरादून, 23 मार्च। कृषि मन्त्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं केन्द्रिय राजस्व विभाग के सचिव डी. बन्धोपाध्याय ने कहा कि कृषकों को अपने परम्परागत ज्ञान को नई तकनीकी के संदर्भ में आगे बढाना होगा तभी कृषक अपनी स्वायत्ता बचाए रख सकता है।

श्री बन्धोपाध्याय आज यहां रूरल लिटिगेशन एवं इन्टाइटलमैन्ट केन्द्र, देहरादून, कट्स, कोलकाता और स्वाती द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किसानों के अधिकार एवं पर्वतीय समुदाय–हम कहां है? विषयक कार्यशाला को संबोधत कर रहे थे। उन्होनें कहा कि स्थानिय लोगो को खाद्यसुरक्षा का महत्व समझना होगा और सूझबूझ के बिना विश्व बाजार में छलांग नहीं लगानी चाहिए क्योंकि विश्व बाजार एवं खुली अर्थव्यवस्था स्थानीय कृषको को पूर्ण रूप से विदेशी उत्पादन पर निर्भर बना रहा है।

उन्होने कहा कि कृषकों के पास 1000 से 2000 साल पुराना ज्ञान है उन्हें अपने इस परम्परागत ज्ञान को नई तकनीकी के संदर्भ में आगे बढाना होगा तभी कृषक अपनी स्वायत्ता को बचाए रख सकता है।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए पत्रकार भरत डोगरा ने कहा कि भूमण्डलीय एवं बाजार अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद का एक नया रूप है। उन्होने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का यही रवैया घोषणात्मक है क्योकि यह जनजातीय लोगों के बीज एवं पेड़ पौधों पर स्थानीय निवासियों के अधिकार पौराणिक है, लेकिन आज विश्व व्यापार संगठन एवं बहुराष्ट्रिय कंपनियों की साजिश की वजह से आज वह बीज पर अपने अधिकारों से वंचित रह रहे है।

उन्होने कहा कि इसका नतीजा यह निकला कि आज स्थानीय लोगों को अपनी ही प्राकृतिक संपदा को ही ऊँची दर देकर खरीदना पड़ रहा है। विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर हस्ताक्षर करने को बाध्य हो रहे है और अगर वह इस समझौते पर हस्ताक्षर करते है तो वह उसकी शोषित नीतियों को अपनाने को बाध्य है जो पूर्ण रूप से बड़े धनी देशों के हितों की रक्षा करती है।

उन्होने कहा कि इससे बड़े किसानों को निश्चित रूप से हानि होगी लेकिन छोटे किसान खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के किसान कहाॅ रह जायेगे? संभवतः हिमालय क्षेत्रों में जीवित रहने का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा। कार्यशाला में मोरी, उत्तरकाशी देहरादून, जौनसार एवं जौनपुर टिहरी गढ़वाल के किसान समुदाय के प्रतिभागी उपस्थित थे। जिन्होंने कार्यशाला से अपेक्षाएं की कि उनकी विश्व व्यापार संगठन की नीतियां, पैटेंट कानून, किसानों का परम्परागत ज्ञान एवं स्थानिय संसाधनों पर लुप्त होते अधिकारों पर बेहतर समझ बन सकें।

डाटमीर एवं मोरी विकास खण्ड से आए भजन सिंह का कहना था कि पहाड़ की खेती को नए बीज और रासायनिक खाद समाप्त कर रहे है और तथाकथित उन्नत खेती अपनाने से हमारे रीति रिवाज एवं परम्पराएं तो लुप्त हो ही रही है साथ ही खाने का संकट भी पैदा हो रहा है।

दोणी गांव, मोरी, उत्तरकाशी से आए अन्य प्रतिभागी पूर्वप्रधान रोजी सिहं का कहना था कि लोगों ने बाहर की बीज अपना कर अत्याधिक नुकसान उठाया है लेकिन अंत में यह किसानों को कहीं का नहीं छोड़ते है। अतः आज हम अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने कि लिए बीज बचाओं आंदोलन की पहल कर रहे हैं।

कार्यशाला में बीज बचाओं आन्दोलन के अग्रणीय रहें कुंवर प्रसून ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों का खजाना है। यही कारण है कि उन्होंने विभिन्न स्थानों की कृषि विविधता को देखते हुए विभिन्न किस्म के बीज विकसित किए। नकदी फसलों, रासायनिक खादों एवं कीटनाशको ने पर्यावरण को और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। पौराणिक कृषि पद्धति एवं अपने बीजों को अपना कर हम विश्व व्यापार संगठन एवं पेटेन्ट कानून शोषित हाथों से अपने को बचा कर रख सकते हैं।

दून दर्पण, 24 मार्च रविवार 2002

किसानों से बेहतर समझ विकसित करने का आहवान

देहरादून – रूरल लिटिगेशन एवं इंटाइटलमेंट केन्द्र ने किसानों के अधिकार एवं पर्वतीय समुदाय विषय पर आयोजित तीन दिवसीय सेमिनार में वक्ताओं ने किसानों से सम्बंधित मुख्य मुद्दो पर बेहतर समझ किस तरह से विकसित किया जाए समेत अन्य विषयों पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए।

यह तीन दिवसीय कार्यशाला रूरल संस्था द्वारा ऑडीटोरियम हाल में आज से शुरू की गई जो कि तीन दिनों तक चलेगी। कार्यालय को सम्बोधित करते हुए भरत डोरगा ने कहा कि भूमण्डलीय एवं बाजार की अर्थव्यवस्था उपनिवेषवाद का एक नया रूप है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तिय संस्थाओ का यही रवैया लोगों के शोषण करने वाला प्रतीत हो रहा है क्योंकि यह जनजातिय लोगों के बीज एवं पेड़ पौधे पर अधिकार समाप्त कर रहे है। उन्होंने कहा कि बीज और पेड़ पौधों पर स्थानीय निवासियों के अधिकार पौराणिक है मगर आज विश्व व्यापार संगठन एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को साजिश की वजह से यहां का नागरिक बीज पर अपने अधिकारों से वंचित हो रहे है। श्री डोंगरा ने कहा कि इस कार्यवाही से बड़े किसानो को निश्चित रूप से हानि होगी मगर छोटें किसानों खासकर पर्वतीय क्षेत्रो के किसान कहां रह जाएंगे यह सोचनीय विषय है? सम्भवतया हिमालय क्षेत्र में तो जीवित रहने का आधार ही इन किसानों का समाप्त हो जाएगा। रूरल केन्द्र में आयोजित कार्य ाला में मोरी उत्तरकाशी देहरादून और जौनसार, टिहरी गढ़वाल के किसानो ने सहभागित की। कार्यशाला में मौजूद डाटमोर एवं मोरी विकास खंड के भजन सिंह का कहना था कि पहाड़ की खेती को नए बीज और रासायनिक खाद समाप्त कर रहे है और तथाकथित उन्नत खेती अपनाने से हमारे रीति रिवाज एवं परम्पराएं तो समाप्त हो ही रहे है। इसके अलावा खाने का भी संकट पैदा हो रहा है। दोणी गांव मोरी उत्तरकाशी से आए प्रतिभागी रोजी सिंह का कहना था कि लोंगो ने कहर के बीज अपना कर अत्यधिक नुकसान उठाया है मगर अंत में यह किसानो को कहीं का नहीं छोड़ता है।

कार्यशलाओं को संम्बोधित करते हुए बीज बचाओ आंदोलन के अग्रणी नेता कुंवर प्रसुन ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रो में स्थानिय किसानों के पास भरपूर ज्ञान का खजाना है और यही वजह है कि उन्होनें विभिन्न स्थानों एवं कृषि विविधता को देखते हुए विभिन्न किस्म के बीज विकसित किए। इसके अलावा नकदी फसलों, रासायनिक खादों एवं कीट नाशकों ने पर्यावरण को और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए ग्रामिण विकास मंत्रालय भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव डी. बन्दोपाध्याय ने कहा कि स्थानीय लोगों को खाद्य सुरक्षा का महत्व समझना होगा और सूझबूझ से विश्व बाजार में छलांग नहीं लगानी चाहिए क्यांकि विश्व वाजार एवं खुली अर्थव्यवस्था स्थानीय कृषको को पूर्ण रूप से विदेशी उत्पादन पर निर्भर बना रहा है। इस मौके पर दर्जनों किसान और अन्य लोग मौजूद थे।

रविवार, 24 मार्च 2002

भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से योजनाएं बनें

देहरादून – किसानों के अधिकार एवं पर्वतीय समुदाय विषय पर आयोजित कार्याशाला का आज समापन हो गया! कार्यशाला में मौजूद किसानों का कहना था कि वे किसानों के लिए बनायी गई सरकारी योजनाओं व नीतियो से पूरी तरह से अनभिज्ञ है और अगर कुछ जानकारी है भी तो वह मैदानी इलाकों के परिपेक्ष्य से ही बनायी गई है।

रूरल संस्था द्वारा किसानों के अधिकार एवं पर्वतीय समुदाय विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ऑडीटोरियम हाल में किया गया। कार्यशाला के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए भरत डोगरा ने चार सुझाव दिए। उनका स्पष्ट कहना था कि सरकार ग्राम पंचायतों व सभाओं को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाए ओर इसके लिए उनको पूरी तरह से अधिकार सम्पन्न बनाया जाए। इसी तरह से वन्य जीव संरक्षण कानून को बदलना होगा क्योंकि पार्क के आसपास और उसके अंदर रहने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे उनकी परम्पराएं और आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो रही है जो कि एक प्रकार से उनके ऊपर अंकुश के समान है। उनका विचार था कि वन्य जीव कानून को इस तरह से बदला जाए कि अन्य जीवों को संरक्षण मिलता रहे और लोगों की भागीदारी भी बनी रहें। पार्क के अंदर रहने वाले लोगों को हटाकर वन्य जीवों का संरक्षण नहीं किया जाना चाहिए।

श्री डोगरा ने एक अन्य सुझाव में कहा कि खेतों की जैव विविधता को भी बचाना होगा। उनका कहना था कि जैव विविधता का खजाना हिमालय क्षेत्र हैं और यहां के खेतों में जैव विविधता के भंडार है जिनको मौके पर जाकर स्वयं किसानों को पहल करनी होगी। इसके अलावा सरकार को भी यह समझना होगा कि इस क्षेत्र में जैव विविधता का खजाना छिपा हुआ है और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि खेतो और वनों की जैव विविधता बची रहे। उन्होने एक अन्य सुंझाव दिया कि सरकार विकास की नीतियों को इस तरह से बनाए कि विस्थापन कम हो और जो जहां पर रह रहा है उसको वहां से हटाने की नौबत न आए। इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने कहा कि चकबंदी वहां पर सरकार लागू न करे बल्कि स्वयं मिल–बैठकर नागरिक फैसला करें जिसको सरकार को मानना चाहिए। कई वक्ताओं ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से यहां पर चकबंदी होनी ही नहीं चाहिए। चकबंदी होने की वजह से खेत फार्म हाऊस का रूप ले लेंगे और लोग एक ही जगह पर बंधकर रह जाएंगे।

वक्ताओं का कहना था कि लोगों का विस्थापन अच्छी प्रकार से होना चाहिए और पार्क के नाम से लोगों को अंदर से निकलना कतई तर्क संगत नहीं है।

नई दिल्ली के डा. गयूर आलम ने पेटेंट कानून का गढ़वाल क्षेत्र के किसानों पर क्या असर पड़ेगा इस पर चर्चा की। यह भी बताया गया कि बीज मिलने में किस तरह को दिक्कतें सामने आएंगी या नहीं आएंगी। अधिकतर किसानो का कहना था कि इस कानून के बाबत थोड़ी और जानकारी की आवश्यकता है। डा. अतुल ने डब्ल्यू. टी. ओ. के बाबत किसानों को बताया। चर्चा में शामिल लोगों का कहना था कि इस मामले में किसान असमंजस की सिथत में है और उनको आशंका है कि इसके तहत कितानों को लपेटा जा रहा हैं। उनका मनना था कि किसानों को अपनी धरोहर को और मजबूती के साथ सुरक्षित रखना होगा।

इसके अलावा जो बहुंत सी चीजें है जिनको किसान छोड़ चुके हैं उनको दोबारा से और मजबूती के साथ प्रयोग करना होगा। मोरी, चकराता और जौनपूर टिहरी गढ़वाल के प्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाने की वकालत की। किसान महिला तस्वीरी रावत ने कहा कि हमें अनुदान के लालच में नहीं पड़ना चाहिए और बदलाव के लिए स्वयं ही पहल करनी होगी। श्रीमती दर्शनी देवी ने कहा कि हमको अपनी बातों को नीति बनाने वालों तक पहुंचाने के लिए संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के नवीन सेन ने कहा कि आज विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर करने की वजह से उसका खतरा हमारे देश के किसानो के ऊपर पड़ रहा हैं। इस मौके पर श्याम लाल, सूरत सिंह, शूरवीर सिंह, विजय पाल, कैलाश पांडे, विक्रम सिंह विप्ट, बीना सजवान अरोना गैरोला, लक्ष्मी असवाल, शराह वेवेस्टर, स्टाजिन डोल्कर, निहारिका सिन्हा, मिता दत्ता, प्रेम सिंह और रोजी सिंह रावत आदि मौजूद थे।

दैनिक जागरण, 25 मार्च, 2002